

न्यायालय जिला कलक्टर (आरबीट्रेटर), सिरौही
बईजलास श्रीमती शुभम चौधरी, आई.ए.एस.

प्रार्थना-पत्र संख्या 14/2023

प्रार्थी

1. श्री जयसिंह पुत्र श्री गोरादान जाति चारण निवासी झांकर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।

बनाम

विपक्षीगण

1. सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट), पिण्डवाडा जिला सिरौही।
2. नेशनल हाईवे ऑथोरिटी जरिये प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इन्डिया पाली जिला पाली।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 सपठित
आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलेशनरल एक्ट, 1996

उपस्थिति :-

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

:: निर्णय ::

दिनांक : 28.08.2024



प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र धारा 3(जी) (5) नेशनल हाईवे एक्ट के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड मजिस्ट्रेट पिण्डवाडा द्वारा मौजा झांकर पटवार हल्का जनापुर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही के खसरा संख्या 564, 569, 573 व 579 की भूमि को नेशनल हाईवे हेतु अवाप्त कर उक्त भूमि के दिए गए मुआवजे से असहमत होकर यह प्रार्थना पत्र आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलेशनरल एक्ट 1996 के तहत आरबीट्रेशन की कार्यवाही हेतु दिनांक 13.03.2012 को प्रस्तुत किया, जो इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 72/2012 अनवान श्री जयसिंह बनाम सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) पिण्डवाडा व अन्य के नाम से दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद सुनवाई पक्षकारान् दिनांक 14.03.2015 को निर्णय पारित किया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2015 के विरुद्ध अप्रार्थी संख्या दो नेशनल हाईवे ऑथोरिटी जरिये प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया पाली द्वारा माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश सिरौही में प्रस्तुत अपील/प्रार्थना पत्र में माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश सिरौही द्वारा दीवानी विविध(आरबीट्रेशन) संख्या 09/2017 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2018 के द्वारा नेशनल हाईवे ऑथोरिटी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित पंचाट आदेश दिनांक 14.03.2015 को निरस्त कर विधि अनुसार आवेदन का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश सिरौही के निर्णय की पालना में प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्ष को नोटिस जारी किए गए, जिस पर प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित ने जरिये वकालतनामा के उपस्थिति दी।

आरबीट्रेटर
जिला कलक्टर, सिरौही

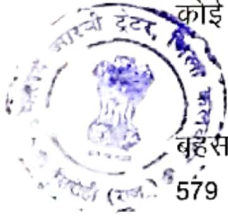
प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई। प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की राजस्व भूमि खसरा संख्या 564, 569, 573 व 579 में से 0.5860 हैक्टेयर मौजा झांकर पटवार हल्का जनापुर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही की भूमि सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) पिण्डवाडा द्वारा उसे कृषि भूमि मानते हुए अवाप्त की जाकर उसका एवार्ड जारी किया है, जो गलत है। यह है कि प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की अवाप्ति की जानकारी होते ही प्रार्थी अप्रार्थी संख्या एक के कार्यालय में उपस्थित होकर क्लेम प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी संख्या एक द्वारा क्लेम में वर्णित तथ्यों व उस पर की गई चर्चा व बहस को कन्सीडर नहीं किया गया है, जिससे एवार्ड जारी करने में त्रुटि हुई है। यह है कि प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि में से खसरा संख्या 569 की भूमि में से 2500 वर्गमीटर भूमि को संपरिवर्तन करवाने हेतु माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय आबूपर्वत के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र सम्पूर्ण पत्रावली सहित प्रस्तुत कर दिया था, जिसमें प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, मौका फर्द, नक्शा आदि दस्तावेजात पेश किए, जिसमें हल्का पटवारी ने उक्त भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के पक्ष में अपनी सहमति जताई और प्रार्थी ने ग्राम पंचायत जनापुर से उक्त भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश किया, तत्पश्चात प्रार्थीगण ने तहसीलदार की अनुशंसा पर उक्त भूमि का संपरिवर्तन शुल्क जमा करवाए, जो उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत की तरफ से जमा करवाए, उसके रकम जमा करवाने की चालान की प्रति व रूपान्तरण पत्रावली में टी.आर.ए. पिण्डवाडा की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रार्थी ने संलग्न पत्रावली की, जिस तहसीलदार पिण्डवाडा ने समस्त पत्रावली का अवलोकन कर उक्त पत्रावली वांछित आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु सिफारिश की टिप्पणी के साथ उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को प्रेषित की, जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त पत्रावली दर्ज कर प्रार्थी को आयन्दा आकर संपरिवर्तन आदेश ले जाने हेतु हिदायत दी, उसके पश्चात प्रार्थी ने कई बार उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क किया, परन्तु प्रार्थी को कोई जवाब नहीं मिला तथा इसी दौरान भारत का राजपत्र दिनांक 25.11.2009 को प्रकाशित हुआ एवं अखबार में दिनांक 12.04.2010 को राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु प्रकाशित हुआ, जिसमें प्रार्थी का खसरा नम्बर भी लिखा आया तथा दिनांक 26.05.2010 को जो राजपत्र अखबार में आया, उसमें प्रार्थी का नाम भी आया था, तब प्रार्थी ने उपखण्ड कार्यालय आबूपर्वत जाकर अपने पत्रावली की प्रमाणित प्रति दिनांक 28.06.2010 को प्राप्त की, जब पता चला कि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा दिनांक 26.10.2009 को ही प्रार्थी की पत्रावली पर यह आदेश कर दिया था कि पिण्डवाडा सेक्शन के ड्राफ्ट 3ए, अधिसूचना में अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है। अतः संपरिवर्तन आदेश जारी किया जाना संभव नहीं होने से पत्रावली संचित की जावे। जबकि प्रार्थी ने संपरिवर्तन हेतु अपना आवेदन दिनांक 15.10.2009 को ही दिया था एवं उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत ने प्रार्थी के समान ही मौजा झांकर के खसरा संख्या 572 रकबा 1.03 बीघा अर्थात् 2500 वर्गमीटर का संपरिवर्तन आदेश श्री जब्बरसिंह के नाम दिनांक 12.10.2009 को किया था। इसी प्रकार जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा भी गांव वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा संख्या 849 व 852 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा का संपरिवर्तन आदेश दिनांक 13.11.2009 को किया है। उक्त दस्तावेजात भी प्रार्थी ने अपने क्लेम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किए थे, लेकिन उक्त सभी तथ्यों को



P

आर्किटेक्टर
जिला कलक्टर, सिरोही

नजरअंदाज कर प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा ने उक्त एवार्ड जारी करने में कानूनन व वाक्यातन गलती की है। इस प्रकार प्रार्थी खसरा संख्या 569 की भूमि का मुआवजा आवासीय दर से प्राप्त करने का अधिकारी था, लेकिन अप्रार्थी संख्या एक ने उक्त भूमि को कृषि भूमि मानकर मुआवजा की गणना करने में त्रुटि की है। यह है कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि शहर पिण्डवाडा के रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया के नजदीक है तथा वर्तमान में उक्त भूमि को नगरपालिका पिण्डवाडा की सीमा में मास्टर प्लान में लिया गया है, जिससे उक्त भूमि काफी कीमती है तथा भविष्य में उक्त सम्पूर्ण भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आनी है। उक्त बहस को भी अवाप्ति अधिकारी ने कन्सीडर नहीं किया। इस प्रकार इसके पास स्थित कृषि भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य करीब 40 लाख रूपए बीघा है तथा आवासीय भूमि का 75/- रूपए वर्गफीट की दर से डी.एल.सी. मूल्य है साथ ही पेड-पौधों इत्यादि के मुआवजा का भी निर्धारण नहीं किया गया है। यह है कि उपरोक्त एवार्ड सन् 2009 की डी.एल.सी. दर से देने भारी भूल की है। उक्त तथ्य को गंभीरता से नहीं लिया है साथ ही कृषि भूमि का मुआवजा निर्धारण करते समय प्रति हैक्टेयर 1,18,500/- रूपए तय किए गए हैं, जो गलत है। यह है कि सक्षम प्राधिकारी ने प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि का बाजार मूल्य को तय नहीं किया गया है। साथ ही उसके अडौस-पडौस में जो रजिस्ट्री हो रही है और मौके पर भूमि की उपयोगिता को नजरअंदाज किया गया है, जबकि मुआवजा भूमि की उपयोगिता के आधार पर दिया जाना चाहिए था। यह है कि धारा 3जी के तहत बाजार मूल्य का विस्तृत अर्थ अधीनस्थ अधिकारी ने नहीं समझा है, जबकि बाजार मूल्य के आधार पर विलिंग सेलर एवं विलिंग पर्चेजर के मध्य होने वाली राशि एक महत्वपूर्ण आधार है, इसके अतिरिक्त लोकेलिटी, प्रोसेबिलिटी, आस-पास की व्यावसायिक गतिविधि को भी मध्यनजर रखना चाहिए था, परन्तु प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लाई जा सकती थी। यह है कि प्रार्थी को उपरोक्त एवार्ड की राशि पर 30 प्रतिशत सोलेशियम की राशि भी दिलाया जाना कानूनन आवश्यक है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा न्यूनतम मुआवजा रूपए 87,10,000/- मय 12 प्रतिशत की ब्याज दर सहित एवं अन्य कोई अनुतोष, जो श्रीमान उचित समझे, दिलाए जाने के आदेश प्रदान करावें।



अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित द्वारा अपनी बृहंस में निवेदन किया गया कि मौजा झांकर के खसरा संख्या- 564, 569, 573 व 579 का सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट), पिण्डवाडा द्वारा मुआवजा राशि का एवार्ड जारी करने में किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं की गई है। यह है कि अधिनियम की धारा 3ए के प्रकाशन की दिनांक को जो भूमि की दर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा तय की गई है, जो कि स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के तहत आनुपातिक प्रणाली अनुसार तय की जाती है और कमेटी का गठन भी नियम 58 के तहत विधिक प्रावधान अनुसार किया जाता है। इसके विपरीत किसी भी तरह की अवधारणा किया जाना उचित नहीं है। अतः भूमि की किस्म कृषि रही है और मौके की व राजस्व अभिलेख के इन्द्राज के आधार पर अवाप्त भूमि की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 3ए के प्रकाशन दिनांक को प्रभावित बाजार दर के आधार पर एवार्ड पारित किया गया है, जिसमें वृद्धि व संशोधन किए जाने की कोई भी अतिरिक्त साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। यह है कि कानूनी रूप से बाजार मूल्य का निर्धारण आसपास की रजिस्ट्री, सेलर परचेजर के मध्य एग्रीमेंट के आधार पर व मौके पर भूमि की उपयोगिता के आधार पर निश्चित नहीं होता है। यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जे

में स्पष्ट प्रावधान है कि उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त भूमि के सम्बन्ध में सोलेटियम के तहत किसी भी तरह की अदायगी मुआवजा बाबत विधिक प्रावधान ही नहीं है, जिसके विपरीत प्रार्थी द्वारा सोलेटियम व ब्याज क्लेम करना कानूनी आधारहीन है। साथ ही प्रार्थी द्वारा वर्णित कथन व मुआवजा गणना विधिक प्रावधानों के विपरीत होकर केवल मात्र काल्पनिक आधारों पर मुआवजा राशि की गणना की गई है, जिसे प्राप्त करने की अधिकारिता प्रार्थी को प्राप्त नहीं है। यह है कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जो भी अभिलेख व तथ्य प्रस्तुत हुए उनका विधि संगत निस्तारण करते हुए अवार्ड पारित किया गया, जिसमें किसी भी तरह की तथ्यात्मक या विधिक त्रुटि नहीं रहीं हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए के विधिक प्रावधानों के तहत अधिसूचना प्रकाशित होकर आपत्तियां आमंत्रित की गईं और अधिनियम की धारा 3सी के तहत आपत्तियों को निस्तारण किया जाकर अधिनियम की धारा 3डी के अनुसार उद्घोषणा जारी की गई, समस्त कार्यवाहियां विधिक प्रावधानों के तहत पूर्ण की गईं, जिसमें प्रार्थीगण को सम्पूर्ण अवसर प्रदान कर आपत्तियों का निस्तारण किया गया। अतः प्रार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण अवसर दिया जाकर आपत्तियों का निस्तारण करते हुए विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत ही अवार्ड पारित किया गया है, जिसमें वृद्धि व संशोधन किए जाने का कोई अतिरिक्त साक्ष्य नहीं है। यह है कि जिला कलक्टर सिरौही द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि अवाप्त अधिकारी द्वारा भूमि के सम्बन्ध में जारी अवार्ड की पत्रावली में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का उल्लेख एवं स्पीकिंग आदेश जारी किया जाना नहीं बताया है, जबकि कानूनन प्रार्थी द्वारा अपने भूमि के रूपान्तरण बाबत जो क्लेम के दस्तावेज दिए हैं, उसमें कानूनी रूप से नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 3ए के प्रकाशन के समय भूमि की किस्म जो होती है, जो कि कृषि थी। इसलिए दस्तावेजात कानूनी रूप से गौण है तथा उन दस्तावेजों के रेकॉर्ड पर लेने पर भी मुआवजा राशि पर तनिक मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि P.Rajamani V/s. Union of India में मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णित किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत सोलेटियम व ब्याज देय नहीं है। इस बाबत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी विभिन्न मामलों में निर्णय किया जा चुका है। अतः पारित अवार्ड विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। यह है कि राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 की धारा 2(xxiii) में बाजार दर को परिभाषित किया गया है और नियम 58 में दर निर्धारण प्रक्रिया, प्रावधान दर्शित है। उक्त विधिक प्रावधान में निर्धारित बाजार दर वास्तविक रूप से व्यावहारिक बाजार दर है और इसी अनुसार मुआवजा आदेश जारी किया गया है। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा जो बाजार दर तय की गई है वह क्षेत्र से सम्बन्धित विक्रय विलेखों के आधार पर अनुपातिक दर निर्धारित कर सम्बन्धित वृद्धि करते हुए वास्तविक रूप से अवाप्त भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है तथा अधिनियम की धारा 3ए की प्रकाशन दिनांक को प्रभावित बाजार दर ही मुआवजा निर्धारण का आधार होती है। यह है कि अवाप्त भूमि की किस्म समस्त अभिलेखों में कृषि दर्ज है और जब तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भूमि की किस्म परिवर्तन का आदेश पारित नहीं किया जाता है या पट्टा परिवर्तन का आदेश पारित नहीं किया जाता है या जारी पट्टे का उपपंजीयन कार्यालय में पंजीकरण नहीं करवाया जाता है तब तक उक्त भूमि की किस्म कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नहीं मानी जाती है और उक्त विधिक प्रावधानों के विपरीत कोई भी आधारित अवधारणा किसी भी न्यायालय द्वारा की जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है एवं पश्चातवृत्ति कार्यवाही अवाप्त भूमि की दर को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रभावित नहीं की जा सकती है। यह है कि




आवट्टिटर
 जिला कलक्टर, सिरौही

अन्य भूमि की किस्म के आधार पर या अन्य भूमि के चपटी लगी हुई भूमि के आधार पर किस्म में परिवर्तन नहीं हो सकता तथा अवाप्त भूमि के पास में रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया स्थित है। उक्त तथ्य इस प्रकार के प्रार्थना पत्र के निवारण करने हेतु विधिक रूप से आधारहीन है, जिससे पारित अवार्ड राशि में वृद्धि के आधार के रूप में भी नहीं आ सकता है तथा साथ ही प्रार्थी को किसी भी तरह की हानि क्षति उक्त अवश्य कार्यवाही के परिणाम स्वरूप कार्य नहीं हुई है। यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक को जो बाजार दर रही है उसी अनुसार अवाप्त भूमि का मुआवजा अदा किया जाने का प्रावधान है। साथ ही धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक के बाद यदि किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो उस बाबत अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि मौजा झांकर पटवार हल्का जनापुर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा संख्या 564 की 0.0670 हैक्टेयर भूमि, खसरा संख्या 569 की 0.2070 हैक्टेयर भूमि, खसरा संख्या 573 की 0.1690 हैक्टेयर भूमि एवं खसरा संख्या 579 की 0.1430 हैक्टेयर भूमि सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) पिण्डवाडा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त की गई थी एवं प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि राजस्व अभिलेख में किस्म खसरा संख्या 564 व 579 की किस्म चा-1 जा-1 एवं खसरा संख्या 569 व 573 की किस्म चा-1 दर्ज थी। चूंकि प्रार्थी द्वारा मौजा झांकर के खसरा संख्या 569 की 1.07 बीघा भूमि में से 2500 वर्गमीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाने बाबत दिनांक 04.11.2009 को उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के समक्ष आवेदन किया, जिसे उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा दिनांक 18.11.2009 को इस आदेश के साथ निरस्त कर दिया था कि मौजा झांकर के उक्त वादग्रस्त खसरा संख्या 569 की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 द्वारा-पाली-पिण्डवाडा सैक्शन के ड्राफ्ट 3ए अधिसूचना में अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है। यहाँ पर भी उल्लेखनीय है कि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा प्रार्थी के उक्त वादग्रस्त खसरा संख्या 569 की भूमि को आवासीय रूपान्तरण करवाने हेतु आवेदन को निरस्त किए जाने के बाद प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील प्रस्तुत किए जाने अथवा नहीं किए बाबत किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं न ही इस सम्बन्ध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा भी किसी भी प्रकार का कोई कथन किया गया है। चूंकि भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित उद्घोषणा दिनांक 10.06.2008 को जारी की गई थी, उस समय उपरोक्त वर्णित अवाप्ताधीन भूमि की किस्म राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार खसरा संख्या 564 व 579 की किस्म चा-1 जा-1 एवं खसरा संख्या 569 व 573 की किस्म चा-1 दर्ज थी। यानिकी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए की उद्घोषणा जारी की गई थी, उस दिन अवाप्त होने वाली भूमि का पूर्ण विवरण दर्ज रहा है, जो कि उक्त आराजी की किस्म कृषि के रूप में दर्ज थी। प्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए की उद्घोषणा जारी होने पर सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट पिण्डवाडा के समक्ष आपत्ति भी प्रस्तुत की थी, जिसे सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट पिण्डवाडा द्वारा दर्ज रजिस्टर कर उस पर विधिवत् सुनवाई की जाकर तत्समय में उक्त भूमि की किस्म कृषि दर्ज होने एवं आवासीय रूपान्तरण के सम्बन्ध में रेकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं होने से प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित भूमि का आवासीय भूमि मानकर मुआवजा देय नहीं



आर्बीट्रेटर

जिला कलेक्टर, सिरोही

किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की उद्घोषणा जारी होने पर प्रार्थी को यह भलीभांति ज्ञात हो गया था कि उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण बाबत आवेदन उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा निरस्त कर दिया गया है, परन्तु इसके पश्चात भी प्रार्थी द्वारा निर्धारित समयवधि में उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत नहीं गई, जिसके लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार है। चूंकि कानूनी रूप से भूमि का संपरिवर्तन आदेश जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा पारित कर रूपान्तरण आदेश जारी नहीं कर दिया जाता है, तब तक किसी भी स्थिति में सम्बन्धित भूमि को रूपान्तरित भूमि नहीं माना जा सकता है, केवल मात्र पटवारी हल्का द्वारा दी गई सहमति, ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं तहसीलदार द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ नहीं माना जा सकता है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का आवासीय रूपान्तरण दर्ज होने बाबत किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा रूपान्तरण आदेश प्रस्तुत नहीं किया है। अतः रूपान्तरण से सम्बन्धित दस्तावेजों के अभाव में प्रार्थी को उक्त भूमि का मुआवजा कृषि भूमि मानकर देय किया गया है। प्रार्थी की उक्त भूमि बाबत जो अधिसूचना राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए के तहत जिस दिनांक को जारी की गई थी उस दिनांक को प्रार्थी का उक्त भूमि पर स्वत्व, स्वामित्व बाबत दस्तावेज का पूर्ण अवलोकन कर एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण कर एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उक्त मुआवजे का निर्धारण किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने की दिनांक के बाद यदि किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो उस बाबत अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त अवाप्तशुदा भूमि का बाजार मूल्य एवं नगरपालिका सीमा में स्थित होने एवं भविष्य में वाणिज्यिक उपयोग में होने के कारण अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का कथन किया गया है, परन्तु प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य यथा नगरपालिका द्वारा जारी पट्टा या वाणिज्यिक रूपान्तरण आदेश इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए जाने से प्रार्थी अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अभिलेख एवं अधिसूचना अनुसार भूमि की किस्म खसरा संख्या 564 व 579 की किस्म चा-1 जा-1 एवं खसरा संख्या 569 व 573 की किस्म चा-1 दर्ज है। ऐसी स्थिति में यदि बाद में प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का आवासीय/वाणिज्यिक रूपान्तरण करवाया भी जाता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अनुसार उसका मुआवजा देय नहीं है, जिसके आधार पर भी प्रार्थी अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा आवासीय दर से प्राप्त करने की अधिकारिता नहीं रखता है। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए के तहत अधिसूचना प्रकाशन की तिथि को रही भूमि की किस्म के आधार पर ही विधिक प्रावधानानुसार प्रार्थी मुआवजा प्राप्त करने की अधिकारिता रखता है, जिसका भुगतान प्रार्थी द्वारा बिना किसी आपत्ति के प्राप्त कर लिया गया है। जहां तक प्रार्थी अधिवक्ता का उक्त अवार्ड पर सोलेशियम की राशि दिए जाने का कथन है। इस सम्बन्ध में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा P.Rajamani V/s. Union of India में पारित निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत सोलेशियम की राशि देय नहीं है। मूल्यांकन प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा अपनी वेल्युवेशन रिपोर्ट विधिक आधार पर ही तैयार की गई है, जिस पर किसी भी प्रकार की कोई संदिग्धता नहीं की जा सकती है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त अवाप्तशुदा भूमि पर लगे पेड़-पौधे इत्यादि के मुआवजे की




आर्जीट्रिक्टर
जिला कलेक्टर, सिरसा

मांग की गई है। चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में अवाप्ताधीन भूमि पर लगे पेड-पौधे इत्यादि का मुआवजा दिया जाने अथवा नहीं दिए जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं किया गया है और न ही इस सम्बन्ध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा किसी भी प्रकार की कोई नजीर पेश की है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत अवाप्ताधीन भूमि पर लगे पेड-पौधे इत्यादि का मुआवजा दिए जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया गया हो।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभिलेखों की रोशनी में स्वीकार योग्य नहीं पाए जाने से निरस्त किया जाता है। मुआवजा राशि में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि किए जाने का आधार नहीं होने से प्रार्थी का क्लेम निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।




(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर, (आरबीट्रेटर)
सिरोही (राज0)